30 हजार क्षमता वाला होगा वाराणसी का क्रिकेट स्टेडियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कराएगा। 13 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाले इस स्टेडियम पर करीब 350 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। इसके लिए यूपीसीए और प्रदेश सरकार के बीच रविवार को अनुबंध हुआ।

रक्षा व अंतरिक्ष क्षेत्र में साथ काम करेंगे यूपी-यूके

डिफेंस सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों से 1642 करोड़ के हुए एमओयू, सीएम योगी ने निवेशकों को मदद और सुरक्षा का दिया भरोसा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में यूपी और ब्रिटेन एक साथ आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलेक्स चाक ने इन्वेस्टर्स समिट के यूनाइटेड किंगडम पार्टनर डिफेंस सेशन में यूपी में इन दोनों क्षेत्र में निवेश की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुए इस सेशन में 1642.61 करोड़ के छह एमओयू हुए।

एलेक्स ने कहा कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी अच्छे हैं। इनको और आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन की कंपनियां यूपी में निवेश करेंगी। उन्होंने कहा कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा क्षेत्र में ब्रिटेन-भारत का एक साथ आगे बढ़ना मौजूदा जरूरत है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रक्षा क्षेत्र में हुए एमओयू की फाइल का आदान प्रदान करते ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलेक्स चाक और यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। -संवाद

सीएम योगी ने ब्रिटेन के निवेशकों को हर तरह की मदद और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी निवेशकों को आमंत्रित किया। सेशन में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, यूके ट्रेड कमिश्नर साउथ एशिया एलन जेमेल, फार्नबोरो फोरम के डॉ. मोहन कौल, ट्रिनहुड लॉ फर्म के निदेशक हरजोत सिंह भी शामिल हुए।

कानपुर में लगेगी रक्षा संयंत्र निर्माण की फैक्टरी

रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल आलोकेश भदौरिया ने बताया कि ब्रिटेन के सहयोग से रक्षा संयंत्र निर्माण की एक फैक्टरी कानपुर में स्थापित होने जा रही है। 300 करोड़ से सैटेलाइट उपकरण निर्माण का प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहा है। उन्होंने निवेशकों को एयरक्राफ्ट इंजन, हथियार निर्माण और आधुनिक तकनीक के इंजन बनाने में भी निवेश का आह्वान किया।

हिंदी बोलकर ब्रिटिश रक्षामंत्री ने चौंकाया, गाना भी गाया

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलेक्स चाक ने हिंदी बोलकर सबको चौंका दिया। उन्होंने 'चोरी-चोरी जहां नहीं... गाना भी गाया। उन्होंने बताया कि मंत्री बनने से पहले लखनऊ के एक निजी स्कूल में चार महीने तक पढ़ाया भी है। उस दौरान मैं कई भारतीयों से मिला। उनकी वजह से जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने बताया कि चौकेडी क्षेत्र के उस स्कूल में जाकर सुकून मिलता है उन लोगों से मिलने। यूपी की तरक्की करते हुए उन्होंने कहा कि यहां भविष्य उज्ज्वल है।

मेट्रो नेटवर्क में अगले साल भारत का होगा दूसरा स्थान: हरदीप

समिट में राष्ट्रीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी व प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा और अन्य। -संवाद

लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगले वर्ष तक भारत मेट्रो नेटवर्क में दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। अभी चीन सबसे लंबे नेटवर्क के साथ पहले स्थान पर है। वर्ष 2040 तक हम भी विकसित देश बन जाएंगे। अब हम बुलेट के लिए सस्ते पर बढ़ने जा रहे हैं। इस योजना की अच्छाई भी उत्तर प्रदेश उसी तरह करेगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का किया था।

टी-इमेजिंग सिटीज एज ग्रोथ सेंटर्स फॉर न्यू उत्तर प्रदेश सत्र में बोले केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। प्रदेश ने सस्ते मकान देने की योजना में उम्मीद से बढ़कर गति दिखाई है। प्रदेश के शहरों की सूरत बदल रही है। लखनऊ, आगरा और वाराणसी इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में वर्ष 2016 में महज 17 हजार पीएम आवास की डिमांड थी, सरकार बदलते ही यह 17 लाख हो गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझसे 10 स्मार्ट सिटी मांगे थे। उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए कई जिला मुख्यालयों को चिह्नित भी कर लिया था, वे बदलाव लाने का जज्बा है। हालांकि, बिना निजी क्षेत्र की मदद केवल सरकार या विभाग कुछ नहीं कर सकता। निजी क्षेत्र को भी अपने निवेश के बदले में लाभ की उम्मीद होती है। बुल

सुबह 5 से 8 होती है मिशन के रूप में सफाई

प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अब यूपी में कूड़े के ढेर से लोगों के घर का पता नहीं चलता है। अफसर और कर्मचारी पुराने ही हैं, लेकिन अब सुबह पांच से आठ बजे तक मिशन के रूप में सफाई अभियान चलता है। यही शहरों की री-इमेजिंग है। मंत्र को मजबूत करेंगे नगर विकास अमृत अभियान, प्रमुख मंत्रित आवास एवं शहरी नियोजन निशिन रमेश गोकर्ण, डिलॉइट के पार्टनर देवाशीष विश्वास, अर्बन डेवलपमेंट चार्ल्स सिमोंस इंस्टीट्यूट की ग्लोबल डायरेक्टर रिचेल फेल्पुन, सीबीआई इंडिया के प्रोग्राम मेजर, भारतीय सिटी के अजीमंदर आर सिंह, राजकोट मेट्रो इंडस्ट्रीज के एमडी विजय कुमार सिंह ने भी संबोधित किया।

लॉजिस्टिक लागत होगी कम, तभी उद्योग कर पाएंगे तरक्की

समिट में लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सेक्टर पर हुआ मंथन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में जब तक लॉजिस्टिक की लागत कम नहीं होगी, उद्योग तरक्की नहीं कर सकेंगे। विकसित देशों में लॉजिस्टिक की लागत करीब आठ फीसदी है जबकि भारत में यह 14 फीसदी तक है। इसमें पांच फीसदी की कमी लाना जरूरी है। यूपी के छह एक्सप्रेसवे, पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी से दीनदयाल तक जलमार्ग और रेलवे का मजबूत नेटवर्क इसमें गेमचेंजर साबित हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रविवार को 'यूपी : द इमर्जिंग वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब ऑफ इंडिया' विषयक सत्र में विशेषज्ञों ने इस पर गहन मंथन किया।

कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने 300 साल तक राज करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया है। वर्तमान में कई देश मंदी के शिकार हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। देश को 30 बरस डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर में दुनिया के टॉप-10 देशों में शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए लॉजिस्टिक की लागत को कम करना है। प्रदेश के शहरीकरण मंत्री नरेंद्र स्वरूप ने कहा कि छह साल पहले वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक का यूपी से कोई नाता नहीं था। अब छह एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और सात बनने जा रहे हैं। यूपी में तीन करोड़ मेट्रिक टन भंडारण के भंडार गृह हैं। इस क्षेत्र में यूपी दूसरे और पंजाब पहले स्थान पर है। सत्र को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी, यूपीसीडा के सीईओ मयूर महेश्वरी, वेलस्पन वन लॉजिस्टिक पार्क के हेड लोकनाथन नाडर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एमडी रविंद्र कुमार जैन ने भी संबोधित किया।

समिट को संबोधित करतीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल। -संवाद

सेक्टरवार निवेश के आंकड़े

सेक्टरवार निवेश	एमओयू	राशि	प्रतिशत	रोजगार
नवीनीकृत ऊर्जा	144	4,47,310	15.47	111374
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग	151	3,85,798	12.41	167768
इंडस्ट्रियल पार्क	2020	328076	11.35	1198349
उच्च शिक्षा	64	2,57,922	8.92	782528
मैन्युफैक्चरिंग	7711	1,97,955	6.85	1549168
लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग	249	159676	5.52	195294
रियल एस्टेट	492	1,24,964	4.32	886799
आईटी जनित सेवा	92	1,12,862	3.90	198526
पर्यटन	397	98,193	3.40	260040
पर्यावरण	1092	54,710	1.89	246808
कर्मी उत्पादन	6	53,495	1.85	12,850
खाद्य प्रसंस्करण	394	69562	2.41	202841
हेल्थकेयर	72	47072	1.63	146984
फूड प्रोसेसिंग	970	37,369	1.29	209851
टेक्सटाइल	1028	30,593	1.06	71,384
खाद्य एवं रसद	73	29,852	1.03	4275
कार्बन	4	25,822	.89	6050
होटल	437	20,272	.72	99608
अक्षयपात्र प्रबंधन	44	20,452	.71	19962
पर्यावरण	174	20,360	.70	133770

पीपीपी मॉडल से संवरेंगे प्रदेश के 48 स्टेशन

48 हजार करोड़ रुपये का होगा निवेश, डीआरएम वर्कशॉप कर निवेशक लाएंगे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 48 रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। ये स्टेशन डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) रूट के होंगे। वहां निवेशक कार्गो टर्मिनल में निवेश करेंगे और उन्हें 33 साल के लिए संचालित करने का अवसर मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में 48 हजार करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतिम दिन रविवार को मार्डनाइजिंग रेल एंड रोड्स ऑफ उत्तर प्रदेश विषय पर सत्र में यह बातें रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहीं। रेलमंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से यूपी में रेलवे के कार्य हो रहे हैं। कोविड के बाद दुनिया भले ही संकट में हो, पर भारत तरक्की कर रहा है। इसमें यूपी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी चर्चा दुनियाभर में है। रेलवे पुल व अंडरपास के लिए यूपी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आवश्यकता होने पर पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। प्रस्तावित कार्गो टर्मिनल को लेकर यूपी के हर जिले में वर्कशॉप कर व्यापारियों को जागरूक किया जाए।

सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड रूप कुमार सोनकर ने कहा कि गाजियाबाद से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तक रेलवे सेक्शन पर अरबों निवेशकों की नई है। जिसकी वजह से पांच-पांच गाड़ियां आगे-पीछे आसानी से चल पा रही हैं। विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 1275 स्टेशनों को अमृत स्टेशन स्कीम में चुना गया है, जिसमें 149 उत्तर प्रदेश के हैं।

लोक निर्माण मंत्री नितिन प्रसाद ने कहा कि रेल रोड के बिना अधूरे है। रेल व रोड के सहयोगपूर्ण के बिना लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। देश को राजनीतिक ही नहीं, औद्योगिक रास्ते भी यूपी से होकर गुजरते हैं। प्रदेश के 21 हाईवे चिह्नित किए जा रहे हैं, जिन्हें पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। एक लाख से अधिक रोजगार की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय उठाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

मर्डनाइजिंग रेल एंड रोड्स ऑफ उत्तर प्रदेश विषय पर सत्र में मौजूद रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, लोक निर्माण मंत्री नितिन प्रसाद व अन्य।

यूपी से महाराष्ट्र, गुजरात के पोर्ट तक माल पहुंचने में अब 48 घंटे ही लगेंगे

डीएफसी के एमडी रविंद्र जैन ने बताया कि डीएफसी यूपी से बीस जिलों से होकर गुजर रहा है। यूपी से माल गुजरात व महाराष्ट्र के पोर्ट्स तक पहुंचने में महज 48 घंटे ही लगेंगे। जबकि पहले इस में सात दिन लगते थे। प्रायोरिटी फ्रेट टर्मिनल बनेगा, जिसके लिए करीब 80 हेक्टेयर जमीन देनी होगी। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपये का निवेश लागेगा।

जनता की भावनाओं को समझ कर फिल्म बनाएं निर्माता : ठाकुर

सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा- ओटीटी व दूसरी भाषा की फिल्मों पर भी यूपी देगा अनुदान, खेल की तरह सिनेमा भी विदेश में तिरंगा फहराने का काम करता है

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म जगत को सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए फिल्म निर्माण करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिल्म से तनाव की स्थिति पैदा न हो। खेल की तरह सिनेमा भी विदेशों में भी तिरंगा फहराने का काम करता है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बड़े पर्दे पर बनने वाली फिल्मों की तरह ही यूपी में बनने वाली ओटीटी पर या किसी भी भाषा की फिल्म पर भी जल्द अनुदान देना शुरू कर देगी।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मीडिया एवं मनोरंजन सत्र में ठाकुर ने कहा कि आज भारत एवं डिजिटल मीडिया क्षेत्र बड़ा संसार हो गया है कि जिसमें हुनर है, उसे कोई रोक नहीं सकता। पहले फिल्मों में केवल अपने चहेतों को बढ़ावा दिया जाता था, पर तकनीक ने ऐसी ताकत दी है कि अब सारा खेल कामगारों का हो गया है। पूरी दुनिया भारत को जानना चाहती है। फिल्म निर्माता यह देखें कि देश की जनता क्या सोच रही है। उदाहरण के तौर पर केवल पार्सल सीरीज में ही सुपर हीरो नहीं है। अपने इतिहास का अध्ययन करें तो पाएंगे कि भारत में तो अतिकाल से ही सुपर हीरो रहे हैं। छोटा भीम आज एनिमेशन में अपना तो सुपर हिट हो गया। आप अपने देश के हीरो पर फिल्में बनाएं, जनता हाथों हाथ लेगी।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मीडिया एवं मनोरंजन सत्र में मौजूद सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद हेमा मालिनी, सांसद रवि किशन, निर्माता-निर्देशक सतीश कौशिक, मधुर भंडारकर, केसी बोकाड़िया और अन्य। -संवाद

हेमामालिनी बोलीं, यूपी में कलाकार सुरक्षित, खुलकर करें निवेश

सांसद हेमा मालिनी ने कहा उत्तर प्रदेश कला, संस्कृति एवं धार्मिक स्थलों का बड़ा केंद्र है। यह स्वतंत्रता सेनानियों, शिक्षाविदों, कलाकारों का प्रदेश है। अभिनय कलाकार से लेकर फैनी आजमी तक ने इसको साबित किया। थिएटर में लोग टिकट खोल लेते हैं क्योंकि यहां की फिल्में देखते हैं। उन्होंने कहा कि सभी अभिनेता नहीं बन सकते। कैमरे के आगे नहीं तो कैमरे के पीछे फिल्म मेकिंग, तकनीशियन, निर्माता-निर्देशक आदि बनकर मुंबई अपना भविष्य बनाएं। सबसे अहम है कि कलाकारों को सुरक्षा चाहिए। यह अब यूपी में है। यहां खुलकर निवेश करें और फिल्म बनाएं।

यूपी में 5000 थियेटर की जरूरत

अभिनेता एवं सांसद रवि किशन ने कहा यूपी में खूब फिल्में बन रही हैं। पीछे से ज्यादा पर्यटक बढ़ाएंगी जा रहे हैं। 2024 से पहले फिल्म सिटी का काम शुरू होगा जो सिनेमा जगत के लिए यहां बहुत बड़ा काम होगा। वहीं अभिनेता एवं निर्देशक सतीश कौशिक ने कहा कि यूपी में और थिएटर चाहिए। यहां केवल 500 थियेटर हैं और 5000 की आवश्यकता है। हम इस पर यहां 500 करोड़ रुपये से काम शुरू कर रहे हैं। निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा कि यूपी में अब सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने से यहां फिल्म निर्माताओं को लाभ होगा।

स्टेडियम को बना दें थियेटर

सतीश कौशिक के प्रस्ताव पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा सुझाव यह है कि यूपी में लगभग पांच हजार इनडोर स्टेडियम हैं। मंगलवार को मनोरंजन में दो दिन थिएटर के रूप में इस्तेमाल करें। इससे होने वाली आय को खिलाड़ियों पर खर्च किया जा सकता है।

मिठाई में वर्क का काम करेगा मेरा निवेश

मशहूर निर्माता-निर्देशक केसी बोकाड़िया ने कहा कि मुझे नोएडा में नहीं, लखनऊ में जमीन चाहिए। मैं 100 करोड़ रुपये का निवेश कर स्टूडियो एवं ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूं। मेरा निवेश छोटा है पर यह मिठाई में वर्क का काम करेगा और इस उद्योग के लिए खास साबित होगा।

माफिया अब फिल्म में नहीं जेल में : निरहुआ

इस मौके पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अब हमें जब फिल्म मेकर कहानी सुनाते हैं कि एक गांव में एक माफिया रहता था तो हम कहते हैं कि अब कहानी बदल दो। मेरी सरकार में माफिया जेल में रहते हैं। भारतवर्ष भी अब बदल रही है। यह सुनकर का मानता है।

फिल्म उद्योग में 1700 करोड़ के निवेश की घोषणा

मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने इस मौके पर बताया कि यूपी की नई फिल्म पॉलिसी के तहत यहां निवेशकों ने 1700 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। इस नीति में 495 फिल्मों का अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसमें 80 फिल्मों को 44 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुदान दिया जा चुका है।

समिट से सरकार ने बदला माहौल, बरकरार रखना चुनौती

एमओयू धरातल पर उतरे तो बदल जाएगी तस्वीर, लक्ष्य से तीन गुना ज्यादा एमओयू साइन कर बनाया रिकॉर्ड

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिकार्ड 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और 94 लाख लोगों को रोजगार का वादा कर सरकार ने प्रदेश का माहौल बदलने का प्रयास किया है। समिट के आयोजन से जहां उद्योग की रंगत बदली है। वहीं शहर व पिछड़े की राजनीति से मरुवाय माहौल भी निवेश और रोजगार की दिशा में बदला है। लेकिन, इस माहौल को लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखना किसी चुनौती से कम नहीं है।

प्रदेश सरकार ने जीआईएस की तैयारी शुरू करने के साथ ही 11.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था। 16 देशों के 21 शहरों में हुए रोड शो में 7.12 लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू साइन होने के बाद सरकार का उत्साह बढ़ा। सरकार ने लक्ष्य को बढ़ाकर 17.13 लाख करोड़ रुपये किया। समिट के समापन पर रविवार तक 33.50 लाख करोड़ रुपये निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। यह राशि शुरुआती निवेश लक्ष्य से तीन गुना और उसके बाद संशोधित लक्ष्य से करीब-करीब दोगुना है। देश-विदेश के 15 हजार से अधिक निवेशकों और उद्यमियों से इतने बड़े निवेश का अनुबंध साइन होने और उनसे करीब-करीब एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद से माहौल बदला है। इर कहीं समिट के जरिये यूपी में होने वाले निवेश और उससे होने वाले विकास और रोजगार सृजन की चर्चा हो रही है।

प्रदेश के एमएसएमई उद्यमियों से लेकर छोटे दुकानदारों, परंपरागत उद्योगों से जुड़े कारीगरों और हस्त शिल्पियों, कुशल और अकुशल श्रमिकों में भी आगामी दिनों में रोजगार की उम्मीद बढ़ी है। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक युवा आबादी को साधने का प्रयास कर रही है, इस समिट ने सबसे ज्यादा उम्मीद की किरण उसी युवा वर्ग में जगाई है। चर्चा शुरू हो गई है कि समिट के आयोजन की तर्ज पर एमओयू को धरातल पर उतारने में भी सरकार सफल रही तो, प्रदेश में तेज विकास नजर आएगा।

आसान नहीं था इतना बड़ा आयोजन

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भले उसके नाम के अनुसार वैश्विक ही हुआ। यूपी ने इतने बड़े स्तर पर समिट का आयोजन आसान नहीं था। प्रदेश सरकार के साथ देश-दुनिया के विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों ने बीते छह महीने से इस समिट के आयोजन में तेजस्व झोंकी। समिट में भारत के सिर देशों का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार के मंत्रियों, मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, आईआईडीसी अरविंद कुमार, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश और एसीईओ प्रभांशु कुमार की टीम के प्रयास से यह संभव हुआ।

सरकार के लिए चुनौती बड़ी : इन्वेस्टर्स समिट 2018 में 4.68 लाख करोड़ के एमओयू में से सरकार ने 75 फीसदी से अधिक एमओयू धरातल पर उतर जाने का दावा किया है। इसे पहली ग्लोबल समिट की बड़ी सफलता के रूप में गिनाया जा रहा है। अब सरकार के सामने 33.50 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारना है। इसमें निवेशकों को आवश्यकता के अनुसार भूमि उपलब्ध कराना, निवेशकों को निवेश स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण दिलाना, निवेशकों की आवश्यकता और अपेक्षा के अनुरूप भू उपयोग परिवर्तन कराना और वह बैठे सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर दिलाना किसी चुनौती से कम न होगा।

निवेश को धरातल पर उतारने में बैंक करें सहयोग

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से यूपी को 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये निवेश 25 क्षेत्रों में हैं, लेकिन बगैर बैंक और वित्तीय संस्थानों के ये धरातल पर नहीं उतर सकते। इसलिए बैंकों का सहयोग बहुत जरूरी है। बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दें, जिससे इन निवेश प्रस्तावों का फायदा यूपी को मिल सके। वे रविवार को समिट के बैंकिंग सेशन में प्रमुख बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इस समय बैंकों का एडवांस क्रेडिट रेशियो 53 फीसदी है। इसका मतलब बैंकों में जितना जमा होता है उसके मुकाबले 53% से एडवांस दिया जाता है। जबकि यह औसत न्यूनतम 60% होना चाहिए। पांच साल पहले तक 46% ही था, इसमें सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की जरूरत है। कार्य प्रणाली खासकर ग्राहकों से संपर्क सुधार कर यूपी के विकास में बैंक और ज्यादा सहयोग दे सकते हैं।

कृषि ऋण के लिए लोन होना जरूरी नहीं : पीएनबी के एमडी अतुल कुमार गोयल ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बैंक काफी गंभीर हैं। पूरी संभावना ऋण के लिए व्यक्ति के पास लोन होना जरूरी नहीं है। सिर्फ उसका किसान होना ही उसे ऋण के योग्य बनाता है। इसमें कंट्रैक्ट पर काम करने वाले किसानों को भी पूरी ऋण मिल सकेगा। एसबीआई के डिप्टी एमडी प्रवीण रायचंद्र ने कहा कि डिजिटाइजेशन होने पर ऋण लेना व लेनदेन करना ज्यादा आसान हो सकेगा। एचडीएफसी बैंक के कंट्री हेड अरविंद जोहरी ने कहा कि बैंक निजी या सरकारी नहीं होते हैं। उनकी पहचान सिर्फ अच्छे और खराब के रूप में ही होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्ता चंद ने डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। चर्चा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक वाही, एक्सिस बैंक के बिजनेस हेड अंकित अग्रवाल और इंडसइंड बैंक के इम्तियाज अहमद सिद्दीकी भी शामिल हुए।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शीर्ष बैंकिंग प्रमुखों से किया आह्वान